Q.1) संविधान के संशोधन की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जैसा कि अनुच्छेद 368 में निर्धारित किया गया है

1. विधेयक के प्रस्ताव को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।
2. विधेयक को प्रत्येक सदन में पूर्ण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए।
3. दोनों सदनों के बीच मतभेद के मामले में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) 1 और 2
c) 2 और 3
d) उपरोक्त में से कोई नहीं

Q.1) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	**असत्य**	**असत्य**
विधेयक को मंत्री या निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है तथा उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।	प्रत्येक सदन में विधेयक को विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, अर्थात, सदन की कुल सदस्यता का बहुमत (यानी 50 प्रतिशत से अधिक) तथा वर्तमान में सदन उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत।	प्रत्येक सदन को पृथक रूप से विधेयक पारित करना होगा। दोनों सदनों के बीच असहमति के मामले में, विधेयक के विचार-विमर्श और पारित होने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

Q.2) निम्नलिखित में से किस प्रावधान के लिए संसद के विशेष बहुमत तथा आधे राज्य विधान सभाओं की सहमति की आवश्यकता है?

1. राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत
2. राष्ट्रपति का चुनाव
3. सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) 1 और 2
c) 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.2) Solution (c)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	**सत्य**	**सत्य**
मौलिक अधिकार और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत संविधान में उन प्रावधानों में से हैं जिन्हें संसद के विशेष बहुमत से संशोधित करने की आवश्यकता होती है।	निम्नलिखित प्रावधानों को संसद के एक विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है तथा एक साधारण बहुमत की आधे राज्य विधानसभाओं से सहमति की भी आवश्यकता होती है: 1. राष्ट्रपति का चुनाव और उसके तरीके। 2. संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्ति का विस्तार।	

	3. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। 4. संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण। 5. सातवीं अनुसूची में कोई भी सूची। 6. संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। 7. संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन के लिए संसद की शक्ति (अनुच्छेद 368 स्वयं)।

Q.3) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. राज्य विधानसभाएँ संविधान में संशोधन के लिए कभी कोई विधेयक या प्रस्ताव नहीं ला सकती हैं।
2. संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति की सीमा मिनर्वा मिल्स मामले के तहत स्थापित की गई थी।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.3) Solution (b)

कथन 1	**कथन 2**
असत्य	**सत्य**
संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद में निहित है। इसलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत, राज्य विधानसभाएं एक मामले को छोड़कर, संविधान में संशोधन के लिए कोई विधेयक या प्रस्ताव नहीं ला सकती हैं, अर्थात, राज्यों में विधान परिषदों के निर्माण या उन्मूलन के लिए संसद से अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित करना।	मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, "चूंकि संविधान ने संसद सीमित संशोधन शक्ति प्रदान की थी, संसद उस सीमित शक्ति के अभ्यास के अंतर्गत नहीं आ सकती है जो विस्तृत शक्ति को एक पूर्ण शक्ति में बदल देती है। वास्तव में, एक सीमित संशोधन शक्ति संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है तथा इसलिए, उस शक्ति की सीमाएं नष्ट नहीं की जा सकती हैं। दूसरे शब्दों में, संसद अनुच्छेद 368 के तहत, अपनी संशोधित शक्ति का विस्तार नहीं कर सकती है, ताकि संविधान को निरस्त करने या कम करने या इसकी बुनियादी विशेषताओं को नष्ट करने का अधिकार प्राप्त हो सके। एक सीमित शक्ति का कार्य उस शक्ति के अभ्यास से नहीं हो सकता है जो सीमित शक्ति को असीमित में बदल देता है। नोट- केशवानंद भारती मामले ने आधारभूत संरचना सिद्धांत को अधिनियमित किया, लेकिन संसद की संशोधित शक्ति पर सीमा को मिनर्वा मिल्स केस द्वारा स्थापित किया गया था।

Q.4) राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य केवल निर्वाचक मंडल में भाग ले सकते हैं।

2. जब कोई विधानसभा भंग होती है, तो सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के लिए योग्य होते हैं, केवल तभी, जब राष्ट्रपति चुनाव से पहले भंग विधानसभा के लिए नए सिरे से चुनाव नहीं हो सकते हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.4) Solution (a)

कथन 1	कथन 2
सत्य	असत्य
राष्ट्रपति का चुनाव सीधे लोगों द्वारा नहीं, बल्कि निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है: 1. संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य; 2. राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य; तथा 3. केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।	जहां एक विधानसभा को भंग कर दिया जाता है, वहां के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के लिए योग्य नहीं होते हैं, भले ही भंग विधानसभा के नए चुनाव राष्ट्रपति चुनाव से पहले न हों।

Q.5) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. अपने पदावधि के दौरान, राष्ट्रपति किसी भी आपराधिक कार्यवाही से प्रतिरक्षित रहता है, यहां तक कि अपने व्यक्तिगत कृत्यों के संबंध में भी।
2. राष्ट्रपति अपने पांच वर्ष के कार्यकाल के बाद भी पद धारण कर सकता है।
3. संसद के किसी भी सदन के नामित सदस्य (nominated members) राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 1 और 3
c) 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.5) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	असत्य
राष्ट्रपति के अपने कार्यकाल के दौरान, राष्ट्रपति किसी भी आपराधिक कार्यवाही से प्रतिरक्षित रहते हैं, यहां तक कि अपने व्यक्तिगत कृत्यों के संबंध में भी।	राष्ट्रपति पांच वर्ष के अपने कार्यकाल के बाद भी तब तक पद संभाल सकते हैं जब तक कि उनके उत्तराधिकारी पदभार नहीं लेते	संसद के दोनों सदनों के नामित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं

Q.6) राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है।
2. अनुदान की कोई माँग उसकी अनुशंसा के अलावा नहीं की जा सकती।
3. वह चुनाव आयोग के परामर्श से संसद के सदस्यों की अयोग्यता के रूप में प्रश्नों पर निर्णय लेता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 1 और 3
c) 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.6) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	सत्य
अपनी कार्यकारी शक्तियों के तहत, वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है तथा अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में अधिकार रखता है।	उनकी वित्तीय शक्तियों के तहत, उनकी सिफारिश के अलावा अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती है।	अपनी विधायी शक्तियों के तहत, वह चुनाव आयोग के परामर्श से संसद के सदस्यों की अयोग्यता के रूप में प्रश्नों पर निर्णय लेता है।

Q.7) निरपेक्ष वीटो (Absolute veto) का प्रयोग, निम्नलिखित में से किस मामले में नहीं किया जा सकता है?

1. निजी सदस्यों के विधेयक
2. संवैधानिक संशोधन विधेयक
3. धन विधेयक

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) केवल 2
c) केवल 3
d) 2 और 3

Q.7) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	सत्य	असत्य
आमतौर पर, निरपेक्ष वीटो (absolute veto) का प्रयोग निम्नलिखित दो मामलों में किया जाता है: (a) निजी सदस्यों के विधेयक के संबंध में (यानी, संसद के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए	संवैधानिक संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति नहीं है। 1971 के 24 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया।	राष्ट्रपति या तो धन विधेयक को अपनी सहमति दे सकता है या धन विधेयक के लिए अपनी सहमति वापस ले सकता है लेकिन संसद के पुनर्विचार के लिए इसे वापस नहीं कर सकता है। इसका अर्थ है कि धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति के

विधेयक जो मंत्री नहीं हैं); तथा (b) कैबिनेट के इस्तीफे के बाद (विधेयकों के पारित होने के बाद लेकिन राष्ट्रपति द्वारा सहमति से पहले) सरकारी बिल के संबंध में और नए कैबिनेट राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि वे ऐसे बिलों के लिए अपनी सहमति न दें।		पास कोई भी निलंबनकारी वीटो शक्ति उपलब्ध नहीं है। वह धन विधेयक के मामले में निरपेक्ष वीटो का प्रयोग कर सकते हैं।

Q.8) सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न मामलों के तहत राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति की जांच की तथा निम्नलिखित सिद्धांतों को निर्धारित किया। इस संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा मौखिक सुनवाई (oral hearing) का अधिकार है।
2. राष्ट्रपति नए सिरे से साक्ष्यों की जांच कर सकता है तथा न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अलग विचार कर सकता है।
3. राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने हेतु बाध्य नहीं है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 1 और 3
c) 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.8) Solution (c)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	सत्य	सत्य

उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न मामलों के तहत राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति की जांच की तथा निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए:
1. दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा मौखिक सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है।
2. राष्ट्रपति नए सिरे से साक्ष्यों की जांच कर सकता है और न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अलग विचार कर सकता है।
3. केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाना है।
4. राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है।
5. राष्ट्रपति न केवल एक ऐसे दंड से राहत दे सकता है जिसे वह अनुचित रूप से कठोर मानता है बल्कि एक स्पष्ट गलती से भी दिए गए को।
6. राष्ट्रपति द्वारा शक्ति के प्रयोग के लिए विशिष्ट दिशानिर्देशों को निर्धारित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की कोई आवश्यकता नहीं है।
7. राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है, सिवाय इसके कि राष्ट्रपति का निर्णय मनमाना, तर्कहीन, गैर-कानूनी या भेदभावपूर्ण न हो।

Q.9) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. राष्ट्रपति के पास संवैधानिक के साथ-साथ स्थितिजन्य विवेकाधिकार भी है।
2. वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेकाधिकार पर कार्य कर सकता है, जब किसी भी दल के पास लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं होता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.9) Solution (b)

कथन 1	कथन 2
असत्य	**सत्य**
यद्यपि राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक विवेकाधिकार नहीं है, उनके पास कुछ स्थितिजन्य विवेकाधिकार हैं। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार से (अर्थात मंत्रियों की सलाह के बिना) निम्नलिखित स्थितियों में कार्य कर सकते हैं: (i) प्रधानमंत्री की नियुक्ति तब होती है जब किसी भी दल के पास लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं होता है या जब कार्यालय में प्रधान मंत्री की अचानक मृत्यु हो जाती है और कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं होता है। (ii) जब वह लोकसभा के विश्वास को प्रमाणित नहीं कर सकता, तो मंत्रिपरिषद का विघटन। (iii) यदि मंत्रिपरिषद ने अपना बहुमत खो दिया है तो लोकसभा का विघटन।	

Q.10) उपराष्ट्रपति के कार्यालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार होता है।
2. संविधान के अनुसार, उस पर 'संविधान के उल्लंघन' के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.10) Solution (a)

कथन 1	कथन 2
सत्य	**असत्य**
उपराष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव की तरह, एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार आयोजित किया जाता है तथा मतदान गुप्त मतदान द्वारा होता है।	उसके निष्कासन के लिए एक औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। उन्हें पूर्ण बहुमत से पारित राज्य सभा के प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है (अर्थात, सदन के कुल सदस्यों का बहुमत) और लोकसभा द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है। लेकिन, जब तक कम से कम 14 दिनों की अग्रिम सूचना नहीं दी जाती है, तब तक इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को नहीं लाया जा सकता है। विशेष रूप से, उनके निष्कासन के लिए संविधान में किसी भी आधार का उल्लेख नहीं किया गया है।

Q.11) 'भारतीय संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और निष्ठा रखना', निम्नलिखित में से किसकी शपथ का हिस्सा है?

1. राष्ट्रपति
2. प्रधान मंत्री
3. मंत्रिपरिषद
4. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1,2 और 3
b) 1,3 और 4
c) 2,3 और 4
d) उपरोक्त सभी

Q.11) Solution (c)

कथन 1	कथन 2	कथन 3	कथन 4
असत्य	सत्य	सत्य	सत्य
राष्ट्रपति की शपथ: 1. कार्यालय को ईमानदारी से निष्पादित करने के लिए; 2. संविधान और कानून का संरक्षण, सुरक्षा और बचाव करना; तथा 3. भारत के लोगों की सेवा और कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करना।	प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की शपथ 1. भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और निष्ठा रखना, 2. भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना, 3. ईमानदारी से और कर्तव्यनिष्ठा से अपने कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन करना, और 4. बिना किसी भय या पक्ष, स्नेह या दुर्भावना के, संविधान और कानून के अनुसार सभी प्रकार के लोगों को समान अधिकार प्रदान करना।		सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ: 1. भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और निष्ठा रखना; 2. भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना; 3. विधिवत और विश्वासपूर्वक और उसकी क्षमता, ज्ञान और निर्णय कार्यालय के कर्तव्यों को बिना किसी डर या पक्ष, स्नेह या दुर्भावना के निभाते हैं; तथा 4. संविधान और कानूनों को बनाए रखना।

Q.12) प्रधान मंत्री कार्यालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. संविधान के अनुसार, एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे छह महीने के लिए प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जिसके भीतर, उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना चाहिए।
2. वह राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत्र पद धारण करता है, इसलिए किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.12) Solution (d)

कथन 1	कथन 2
असत्य	**असत्य**
1997 में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे छह महीने के लिए प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जिसके भीतर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना चाहिए; अन्यथा, उसका प्रधान मंत्री पद समाप्त हो जायेगा। नोट- संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।	प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत्र के दौरान पद पर रहते हैं। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को हटा सकता है। जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। हालांकि, अगर वह लोकसभा का विश्वास खो देता है, तो उसे इस्तीफा देना चाहिए या राष्ट्रपति उसे हटा सकते हैं।

Q.13) प्रधानमंत्री के कार्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

a) वह राय के अंतर के मामले में राष्ट्रपति को एक मंत्री को बर्खास्त करने की सलाह देता है।
b) वह मंत्रियों के वेतन और भत्ते का निर्धारण करता है।
c) वह वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है।
d) वह लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सलाह देता है।

Q.13) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3	कथन 4
सत्य	**असत्य**	**असत्य**	**असत्य**
प्रधानमंत्री को केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं: 1. वह उन लोगों की सिफारिश करता है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति केवल उन व्यक्तियों को मंत्री के रूप में नियुक्त कर सकते हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा अनुशंसित हैं। 2. वह मंत्रियों के बीच विभिन्न विभागों का आवंटन और फेरबदल करता है। 3. वह किसी मंत्री को इस्तीफा देने या राय के अंतर के मामले में उसे हटने	मंत्रियों के वेतन और भत्ते समय-समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।	वह राष्ट्रपति को भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों और ऐसे अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में सलाह देता है।	अध्यक्ष (Speaker) का चुनाव लोकसभा द्वारा उसके सदस्यों में से किया जाता है (जैसे उसकी प्रथम बैठक के बाद हो सकता है)।

की सलाह देने के लिए कह सकता है। 4. वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है और उसके निर्णयों को प्रभावित करता है। 5. वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों का मार्गदर्शन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय करता है। 6. वह पद से इस्तीफा देकर मंत्रिपरिषद के पतन का कारण बन सकता है।			

Q.14) 91 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रस्तुत किया गया था?

a) राष्ट्रपति को किसी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद की आवश्यकता हो सकती है तथा राष्ट्रपति इस तरह के पुनर्विचार के बाद प्रदान की गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा।
b) मंत्रिपरिषद में प्रधान मंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी।
c) दलबदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान
d) लोकसभा और राज्य विधान सभा चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।

Q.14) Solution (b)

कथन a	**कथन b**	**कथन c**	**कथन d**
असत्य	**सत्य**	**असत्य**	**असत्य**
चालीसवां (40) संशोधन अधिनियम, 1978- पुनर्विचार के लिए कैबिनेट की सलाह हेतु राष्ट्रपति को वापस भेजने का अधिकार। लेकिन, राष्ट्रपति पर पुनर्विचार की सलाह बाध्यकारी होती है।	इक्यानवे (91) संशोधन अधिनियम, 2003- केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधान मंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी (अनुच्छेद 75 (1 ए))।	बावनवाँ (52) संशोधन अधिनियम, 1985- दलबदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान किया गया और इस संबंध में विवरण सहित एक नई दसवीं अनुसूची जोड़ी गई।	एकसठवां (61) संशोधन अधिनियम, 1989- लोकसभा और राज्य विधान सभा चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया।

Q.15) संघ कार्यकारिणी (union executive) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना कार्यकारी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता।
2. मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
3. एक मंत्री जो संसद के एक सदन का सदस्य होता है, उसे दूसरे सदन में मतदान करने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 1 और 3
c) 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.15) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन
सत्य	सत्य	असत्य
सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, अनुच्छेद 74 अनिवार्य है तथा इसलिए, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना कार्यकारी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है।	अनुच्छेद 75 स्पष्ट रूप से बताता है कि मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है इसका अर्थ यह है कि सभी मंत्री अपने सभी कार्य के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।	एक मंत्री जो संसद के एक सदन का सदस्य होता है, उसे बोलने और दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन वह केवल उसी सदन में मतदान कर सकता है, जिसके वह सदस्य हैं।

Q.16) मंत्रिपरिषद में तीन श्रेणी के मंत्री होते हैं, अर्थात् कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, और उप मंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

1. राज्य मंत्रियों को मंत्रालयों / विभागों का स्वतंत्र प्रभार नहीं मिल सकता है।
2. राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं ले सकते, जब तक कि विशेष रूप से आमंत्रित नहीं किया जाता है।
3. उप मंत्री कैबिनेट के सदस्य बन सकते हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 1 और 3
c) 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.16) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	सत्य	असत्य
राज्य मंत्रियों को या तो मंत्रालयों / विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है या उन्हें कैबिनेट मंत्रियों से संबद्ध किया जा सकता है।	राज्य मंत्री कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं तथा कैबिनेट की बैठकों में शामिल नहीं होते हैं जब तक कि विशेष रूप से आमंत्रित नहीं किया जाता है जब उनके मंत्रालयों / विभागों से संबंधित कुछ को कैबिनेट द्वारा माना जाता है।	उप मंत्री कैबिनेट के सदस्य नहीं हैं तथा कैबिनेट की बैठकों में शामिल नहीं होते हैं।

Q.17) 'मंत्रिपरिषद' और 'मंत्रिमंडल' शब्दों का उपयोग अक्सर परस्पर विनिमय के लिए किया जाता है, हालांकि उनके बीच एक निश्चित अंतर है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बीच अंतर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. मंत्रिपरिषद के पास मंत्रिमंडल की तुलना में कोई सामूहिक कार्य नहीं होता है जो आम तौर पर सप्ताह में एक बार बैठक करके जानकारी प्राप्त करता है और सरकारी व्यवसाय के संचालन के बारे में निर्णय लेने के लिए होता है।
2. मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल द्वारा अपने निर्णयों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करती है।
3. मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल की तुलना में मंत्रियों की संख्या के संदर्भ में एक व्यापक निकाय है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 1 और 3
c) 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.17) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	असत्य	सत्य
सरकारी कार्य संचालन हेतु, मंत्रिपरिषद एक निकाय के रूप में नहीं मिलती है। इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं है। कैबिनेट, एक निकाय के रूप में, अक्सर मिलता है तथा जो आम तौर पर सप्ताह में एक बार बैठक करके जानकारी प्राप्त करता है और सरकारी व्यवसाय के संचालन के बारे में निर्णय लेने के लिए होता है। इस प्रकार, इसके सामूहिक कार्य हैं।	मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद द्वारा अपने निर्णयों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करता है।	मंत्रिपरिषद एक व्यापक निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल एक छोटा निकाय है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं।

Q.18) कैबिनेट समितियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. ये व्यापार के नियमों (Rules of Business) के तहत स्थापित किए गए हैं।
2. यदि प्रधान मंत्री किसी समिति का सदस्य है, तो वह सदैव इसकी अध्यक्षता करता है।
3. संसदीय मामलों की समिति की अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 1 और 3
c) 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.18) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	असत्य
मंत्रिमंडल समितियाँ अतिरिक्त	वे ज्यादातर प्रधान मंत्री के नेतृत्व में हैं।	संसदीय मामलों की समिति

संवैधानिक हैं। दूसरे शब्दों में, संविधान में उनका उल्लेख नहीं है। हालांकि, व्यापार के नियम उनकी स्थापना के लिए प्रावधान प्रदान करते हैं।	कुछ बार अन्य कैबिनेट मंत्री, विशेष रूप से गृह मंत्री या वित्त मंत्री भी इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन, यदि प्रधान मंत्री किसी समिति का सदस्य होता है, तो वह निश्चित रूप से इसकी अध्यक्षता करता है।	वर्तमान में रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में है।

Q.19) भारत के महान्यायवादी के कार्यालय के लिए योग्यता संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. उसे भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. वह राष्ट्रपति के विचार में पाँच वर्षों के लिए किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या दस वर्षों के लिए किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता या एक प्रतिष्ठित न्यायविद रहा होगा।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.19) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
महान्यायवादी को एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। दूसरे शब्दों में, वह भारत का नागरिक होना चाहिए तथा वह राष्ट्रपति के विचार में पांच वर्ष के लिए किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या दस वर्ष के लिए किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता या एक प्रतिष्ठित न्यायविद रहा होगा।	

Q.20) भारत के महान्यायवादी के कार्यालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. महान्यायवादी उन सभी विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं का आनंद लेता है जो संसद के सदस्य के लिए उपलब्ध हैं।
2. अपने निजी कानूनी व्यवहार में, वह भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक अभियोगों में आरोपी व्यक्तियों की रक्षा कर सकता है।
3. वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) 1 और 2
c) 1 और 3
d) केवल 2

Q.20) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	असत्य	असत्य
महान्यायवादी उन सभी	कर्तव्य की किसी भी जटिलता और संघर्ष	महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का

विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं का आनंद लेता है जो संसद के सदस्य के लिए उपलब्ध हैं।	से बचने के लिए महान्यायवादी पर सीsमाएं लगाई जाती हैं। उनमें से एक है, उसे भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मुकदमों में आरोपी व्यक्तियों का बचाव नहीं करना चाहिए।	सदस्य नहीं है। सरकारी स्तर पर कानूनी मामलों की देखभाल के लिए केंद्रीय कैबिनेट में एक अलग कानून मंत्री होता है।

Q.21) विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई है

a) विश्व आर्थिक मंच (WEF)
b) अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU)
c) इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट (IMD)
d) इकोनॉमिस्ट इंटेलीजेन्स यूनिट (EIU)

Q.21) Solution (c)

- इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट (IMD) वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा उत्पादित विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 63 अर्थव्यवस्थाओं की क्षमता और तत्परता को मापती है, जो व्यवसाय, सरकार और व्यापक समाज में आर्थिक परिवर्तन के लिए एक प्रमुख चालक के रूप में डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने और तलाशने से संबंधित है।
- भारत 2018 में 48 वें स्थान से बढ़कर 2019 में 44 वें स्थान पर पहुंच गया क्योंकि देश ने पिछले साल की रैंकिंग की तुलना में सभी कारकों - ज्ञान, प्रौद्योगिकी और भविष्य की तत्परता में समग्र सुधार किया है।
- अमेरिका को विश्व की सबसे डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थान दिया गया था, जिसके बाद सिंगापुर दूसरे स्थान पर था। इस सूची में स्वीडन तीसरे स्थान पर रहा, उसके बाद क्रमशः 4 वें और 5 वें स्थान पर डेनमार्क और स्विट्जरलैंड थे।

Q.22) निलिगिरी इबेक्स (Niligiri Ibex) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है / हैं?

1. यह दक्षिणी पश्चिमी घाटों के लिए स्थानिक है, केवल केरल और तमिलनाडु राज्यों में पाया जाता है।
2. इसे IUCN रेड सूची के तहत लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
3. मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान में अन्य राष्ट्रीय उद्यानों के बीच वनों में सबसे अधिक नीलगिरी इबेक्स आबादी है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.22) Solution (a)

कथन 1	**कथन 2**	**कथन 3**
सत्य	**सत्य**	**असत्य**
नीलगिरि ताहर / नीलगिरि Ibex नीलगिरि पहाड़ियों और पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग के लिए स्थानिक है।	वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में सूचीबद्ध है तथा IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय है। यह	अनुमानित 700-800 नीलगिरि ताहर एराविकुलम नेशनल पार्क (केरल) है, जो इसे विश्व की सबसे

केवल तमिलनाडु और केरल में पाया गया है।	तमिलनाडु का राज्य पशु है।	बड़ी वन्य आबादी बनाता है।

Q.23) 'जल क्रांति' अक्सर समाचारों में देखी जाती है, किससे संबद्ध है

a) हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन
b) जीवन की बढ़ती लागत के प्रतिउत्तर में पूरे चिली में नागरिक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
c) स्पेन के कैटेलोनिया क्षेत्र में स्वतंत्रता-समर्थक प्रदर्शनकारी
d) जल तनाव की बढ़ती स्थिति को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया में एक अभियान।

Q.23) Solution (a)

- लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों ने 2019 में हांगकांग को हिलाकर रख दिया है जिसे "जल क्रांति" के रूप में जाना जाता है।
- प्रदर्शनकारियों ने "पानी होने" की रणनीति का पालन किया है - पानी की तरह निराकार, आकारहीन होने के लिए जो बह सकती है या दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है।
- विरोध कई बार सौम्य और शांत रहा है, लाखों नागरिक शांति से सड़कों पर रहते हैं और फिर चले जाते हैं। अन्य समय में, वे एक संघर्ष में फंस गए थे क्योंकि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई थीं
- 2014 की "अम्ब्रेला क्रांति" - जब 79 दिनों के लिए केंद्रीय हांगकांग के कुछ हिस्सों पर आदर्शवादी युवाओं ने अधिग्रहित कर लिया तो इस क्षेत्र में सार्वभौमिक मताधिकार का आह्वान किया गया।

Q.24) शैलेश नायक समिति ने किसके नियमन के लिए सिफारिशें दीं

a) भारत में क्रिप्टो मुद्राएँ
b) मीडिया की कार्यप्रणाली
c) तटीय विनियमन क्षेत्र
d) संयोजन दवा या एक निश्चित खुराक संयोजन (FDC)

Q.24) Solution (c)

- तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) 2018 की अधिसूचना शैलेश नायक समिति की सिफारिशों पर आधारित थी।
- समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं जो CRZ क्षेत्रों में सुरक्षा के कई पहलुओं को संकीर्ण कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, यह सीआरजेड III (ग्रामीण क्षेत्रों सहित अपेक्षाकृत अविभाजित क्षेत्र) को घनी आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों और कम ग्रामीण क्षेत्रों में "गैर विकास क्षेत्र" (no development zone) के माध्यम से 50 मीटर तक कम करता है।

Q.25) प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन (NEAT) योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है / हैं?

1. इस योजना का उद्देश्य सीखने की आवश्यकताओं के अनुसार अधिक व्यक्तिगत और अनुकूलित बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करना है।
2. यह एक सार्वजनिक निजी भागीदारी योजना है।
3. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) एनईएटी कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगी।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1
c) केवल 2 और 3

d) 1, 2 और 3

Q.25) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	सत्य
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्च शिक्षा में बेहतर शिक्षण परिणामों के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी के लिए एक नए राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन (एनईएटी) की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य सीखने की आवश्यकताओं के अनुसार अधिक व्यक्तिगत और अनुकूलित बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना है।	एनईएटी एक सार्वजनिक निजी भागीदारी योजना है। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से एडेप्टिव लर्निंग में प्रौद्योगिकियों के विकास में काम करने वाली एडटेक (EdTech) कंपनियों के साथ एक राष्ट्रीय गठबंधन बनाने का प्रस्ताव करता है।	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) एनईएटी कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगी।

Q.26) 'वेडेल गायर' (Weddell Gyre) हाल ही में समाचारों में था। यह कहाँ स्थित है?

a) हिंद महासागर
b) दक्षिणी महासागर
c) प्रशांत महासागर
d) आर्कटिक महासागर

Q.26) Solution (b)

वेडेल गायर (Weddell Gyre) उन दो गायरों में से एक है जो दक्षिणी महासागर के भीतर मौजूद हैं। गाइरे का निर्माण अंटार्कटिक ध्रुवीय धारा (Circumpolar Current) और अंटार्कटिक महाद्वीपीय शेल्फ के बीच अंत:क्रिया से हुआ है। गायर वेडेल सागर में स्थित है, और दक्षिणावर्त घूमता है। अंटार्कटिक ध्रुवीय धारा (एसीसी) के दक्षिण में और अंटार्कटिक प्रायद्वीप से उत्तर-पूर्व में फैलता है, गायर एक विस्तारित बड़ा चक्रवात है।

नोट - गायरों (gyres) की अवधारणा को देखें।

सोचिए!

- आंद्रेक्स प्रोजेक्ट

Q.27) 'ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स' द्वारा जारी किया गया है

a) इकोनॉमिस्ट इंटेलीजेन्स यूनिट (EIU)
b) विश्व आर्थिक मंच
c) हेरिटेज फाउंडेशन
d) इनसीड (INSEAD)

Q.27) Solution (a)

भारत में नई दिल्ली और मुम्बई इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2019 के अनुसार 140 शहरों में से 118 वें और 119 वें स्थान पर हैं।

Q.28) 'केंद्रीय प्रतिकूल सूची' (Central Adverse List) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. वे असम में मतदाताओं की श्रेणी के हैं, जो उचित नागरिकता संबंधी दस्तावेज़ों की कथित कमी के कारण सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित (disenfranchised) किए गए हैं।
2. वे विदेशी अधिनियम (Foreigners Act) के तहत विशेष न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

सही कथनों का चयन करें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.28) Solution (d)

प्रतिकूल सूची (Adverse List)

समाचार: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय मूल के 312 सिखों के नाम एक "प्रतिकूल सूची" से हटा दिए हैं, और केवल दो व्यक्ति सूची में बने हुए हैं।

इनके बारे में

- 1980 के दशक में अलगाववादी आंदोलन के दौरान, कुछ सिख गिरफ्तार होने से बचने के लिए भारत छोड़कर विदेशी नागरिक बन गए। 2016 तक उन्हें ब्लैकलिस्ट में रखा गया था, जिससे वे वीजा सेवाओं का लाभ उठाने या भारत लौटने के लिए अयोग्य हो गए थे।
- केंद्रीय प्रतिकूल सूची खुफिया एजेंसियों द्वारा तैयार की गई थी तथा विदेशों में विभिन्न भारतीय मिशनों के साथ उपलब्ध थी।
- सूची में शामिल लोगों को वीजा के लिए अयोग्य बनाने के अलावा, यह उनके परिवार के सदस्यों की संभावनाओं को भी बाधित करता है।
- दो वर्ष की अवधि के लिए आवेदन करने और सामान्य वीजा प्राप्त करने के बाद, भारतीय वीजा की नागरिकता (ओसीआई) कार्डधारक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले सभी श्रेणी के भारतीय लॉन्ग टर्म भारतीय वीजा जारी करने के लिए पात्र हो जाएंगे।

Q.29) निम्न में से कौन सा देश 'CARICOM समुदाय' का पूर्ण सदस्य नहीं है।

1. जमैका
2. कोलम्बिया
3. मेक्सिको
4. वेनेजुएला

सही कूट का चयन करें:

a) 1, 2 और 3
b) 2, 3 और 4
c) 1, 3 और 4
d) 1, 2 और 4

Q.29) Solution (b)

कैरेबियन समुदाय (CARICOM या CC) पंद्रह कैरेबियन देशों और निर्भरता का एक संगठन है, जिसके सदस्यों के बीच आर्थिक एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक उद्देश्य हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एकीकरण के लाभ समान रूप से साझा किए जाते हैं, और विदेश नीति का समन्वय होता है।

पूर्ण सदस्य - एंटीगुआ और बारबुडा, द बहामास, बारबाडोस, बेलीज, डोमिनिका, ग्रेनाडा, गुयाना, हैती, जमैका,
मोंटसेरत, सेंट किट्स और नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, सूरीनाम, और त्रिनिदाद और टोबैगो।

एसोसिएट सदस्य - बरमूडा, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप, केमैन द्वीप, तुर्क और कैकोस द्वीप

पर्यवेक्षक - अरूबा, कोलंबिया, कुराकाओ, डोमिनिकन गणराज्य, मैक्सिको, प्यूर्टो रिको, सेंट मार्टेन, वेनेजुएला

Q.30) 'फहीमा शिरिन बनाम केरल राज्य' अधिनिर्णय किससे संबंधित है

a) विवाह का अधिकार
b) इंटरनेट का अधिकार
c) संपत्ति का अधिकार
d) मत देने का अधिकार

Q.30) Solution (b)

केरल उच्च न्यायालय ने अपने अधिनिर्णय में फहीमा शिरीन आरके बनाम केरल राज्य और अन्य को स्पष्ट रूप से, आश्वस्त रूप से घोषित करके एक बड़ा कदम उठाया है कि इंटरनेट का उपयोग करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निजता के अधिकार का एक मौलिक अधिकार है।